डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 फरवरी, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 फरवरी, 2024

| वर्ष 67 | अंक 18 | भोपाल | 16 फरवरी, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ से मध्यप्रदेश को 7550 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी

निमाड़ अंचल को दी टंटिया मामा विश्वविद्यालय की सौगात

इन्दौर : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ जिले के ग्राम गोपालपुरा में जनजातीय महा सम्मेलन कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश को 7550 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर सौगात दी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर रेलवे एवं नेशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिसमें रतलाम रेलवे के 27.15 करोड रूपये से होने वाले पुर्नविकास के अंतर्गत 12 मीटर चौड़ा फूट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा, जिससे शहर के दोनों हिस्से का एकीकरण होगा। उन्होंने 25.18 करोड लागत से मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुर्नविकास कार्य का शिलान्यास किया, जिससे स्टेशन उन्नत होगा तथा रेल यात्रा सुगम होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 604 करोड रूपये की लागत वाली इन्दौर-देवास-उज्जैन रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 236.82 करोड की लागत से निर्मित इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर तथा 51 किलोमीटर लंबी बरखेड़ा बुधनी इटारसी लाइन 2137 करोड़ की लागत से निर्मित परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।

इन परियोजनाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सीएम राइस स्कूल का लोकार्पण, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिला झाबुआ लागत 27 करोड़, लिगेसी वेस्ट डंपिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार परियोजना का लोकार्पण 25.19 करोड़ की लागत, तलावड़ा ड्रिंकिंग वाटर परियोजना का लोकार्पण किया। इससे धार एवं रतलाम जिले के 1011 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंदौर संभाग के निमाड़ अंचल को 170 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले टंटिया मामा विश्वविद्यालय की सौग़ात दी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सिंगल क्लिक से प्रधानमंत्री आहार अनुदान योजना की 1 लाख 50 हजार हितग्राहियो को प्रदान की। उन्होंने 1 लाख 75 हजार अधिकार अभिलेख स्वामित्व योजना के अंतर्गत हितग्राहियो को प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उक्त परियोजनाओं की चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं पर आधारित लघु फ़िल्म का प्रदर्शन हुआ।

कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल श्री मंगु भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय जनजातीय कार्य विभाग मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, सांसद खजुराहो श्री वी डी शर्मा, सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया, वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, मुख्य सचिव वीणा राणा सहित मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी गण सहित गणमान्य जन उपस्थित थे।

सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने इंदौर में ली संभागीय समीक्षा बैठक

प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा

सहकारिता विभाग अब नए कलेवर-नयी सोच के साथ करेगा कार्य

बहुवर्षीय रोड मैप बनाया जायेगा

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। समाज, परिवार, प्रदेश और देश समन्वय और परस्पर सहयोग के बगैर नहीं चल सकते हैं। सहकारिता की समाज में अहम भूमिका है। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। रोजगार के नए अवसर सृजित किये जायेंगे।

यह बात मंत्री श्री सारंग ने इंदौर में सहकारिता और इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक में कही।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में बढ़ेगी कुशलता और दक्षता : मुख्यमंत्री

मंत्रालयों और विभागों के साथ तालमेल और समन्वय को सीखने का अवसर

नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाला प्रबोधन कार्यक्रम

जन–प्रतिनिधि और नीति आयोग के विशेषज्ञों का हुआ उद्‌बोधन

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मंत्रि–परिषद का ओरिएंटेशन प्रोग्राम

भोपाल। मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में कुशलता और दक्षता आयेगी। यह मंत्रि–परिषद की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाला प्रबोधन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट में मंत्रि–परिषद के दो दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहें थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य की मंत्रि–परिषद के निर्णय से प्रदेश की समूची जनता प्रभावित होती है। इसलिए मंत्रि–परिषद के सदस्यों का समय–समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण से शासन की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा जिससे प्रशासन में कसावट आयेगी और इसका सीधा लाभ मंत्रि–परिषद के निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की जनता को मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रशिक्षण से मंत्रि–परिषद के सदस्यों को भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों के साथ तालमेल और समन्वय को सीखने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ जन–प्रतिनिधि और नीति आयोग के विशेषज्ञों के उद्‌बोधन से मंत्रि–परिषद का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे न सिर्फ शासन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन को भी अनुशासित और सफल बनाने में मदद मिलेगी।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मध्यप्रदेश द्वारा रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी संस्थान के साथ जन–प्रतिनिधियों के लिये दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम 'लीडरशिप समिट' चल रही है। समिट के पहले दिन जन–प्रतिनिधियों के ओरिएंटेशन के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव, वरिष्ठ जन–प्रतिनिधि और नीति आयोग के विशेषज्ञों के उद्‌बोधन के विभिन्न सत्र आयोजित हुए।

मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट के पहले दिन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी संस्थान के कार्यकारी संचालक डॉ. जयंत कुलकर्णी ने प्रशिक्षण की रूपरेखा और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा, श्री शिवप्रकाश और श्री व्ही. सतीश ने शासन में नेतृत्व और कुशलता पर अपने विचार रखें। अंतिम सत्र में "आकांक्षाएँ एवं संकल्प भारत सरकार की अहम पहल" विषय पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग भारत सरकार के श्री आनंद शेखर ने बताया कि नीति आयोग मध्य प्रदेश के साथ मिलकर 4 डिस्टिंक्ट एरिया में कार्य कर रहा है। सतत विकास के लक्ष्य जिसका नीति आयोग कस्टोडियन है, उसमें मध्यप्रदेश के साथ मिल कर दिनों दिन प्रगति की जा रही है। साथ ही "तनाव प्रबंधन" पर डॉ. विक्रांत तोमर का उद्‌बोधन हुआ।

लीडरशिप समिट के दूसरे दिन 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक विभिन्न सत्रों का आयोजन हुआ। इनमें "विधायी कार्य–प्रणाली", "अवसर एवं चुनौतियाँ", "आकांक्षाएँ एवं संकल्प–भारत सरकार की अहम पहल" एवं "प्रौद्योगिकी एवं सुशासन" विषय पर सत्रों का आयोजन हुआ।

इन सत्रों को विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्वेता सिंह, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, नगरीय आवास एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय संबोधित किया।

प्रदेश में तुअर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा : मुख्यमंत्री डॉ.यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से सीएसीपी के प्रतिनिधि मंडल की भेंट

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में तुअर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार का प्रोत्साहन मिलने से प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

प्रतिनिधि मंडल में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष प्रो. विजय पॉल शर्मा तथा आयोग के सदस्य डॉ. नवीन पी सिंह, श्री अनुपम मित्रा और श्री रतन लाल डागा शामिल थे। इस अवसर

पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता के माध्यम से करोड़ो लोगों को स्वरोजगार के साथ जोड़ने का एक मज़बूत तंत्र खड़ा किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण की योजना का शुभारंभ किया

मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया और सहकारिता से डाली समृद्ध ग्राम की नींव

पैक्स से लेकर पूरी कॉपरेटिव व्यवस्था का मोदी सरकार ने किया आधुनिकीकरण

डिजिटलीकरण की मदद से गांव-गांव तक पहुंचेगा सहकारिता मंत्रालय

अब पूरा सहकारिता क्षेत्र डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर अपने विस्तार के लिए तैयार है

ARDBs और PACS मिलकर आधुनिक कृषि के लिए किसानों को मध्य और लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध करा सकें इस दिशा में काम किया जा रहा है

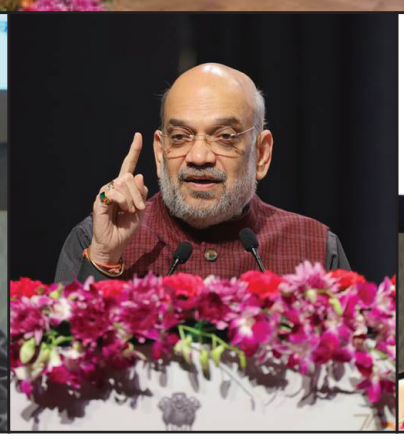

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय (Registrar of Co-operative Societies) और कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों (Agriculture and Rural Development Banks) के कंप्यूटरीकरण की योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री बी एल वर्मा और सचिव, सहकारिता मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विज़न को साकार करने की दिशा में आज हम एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर सहकारिता से जुड़े लोगों की बहुत पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 10 साल में देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए मोदी जी ने 2 महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों के जीवनस्तर को उठाने के लिए अकल्पनीय सहायता की है, जिससे लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता के माध्यम से करोड़ो लोगों को स्वरोजगार के साथ जोड़ने का एक मज़बूत तंत्र खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि एक विस्तृत विज़न के साथ दोनों कामों को एकसाथ करते हुए मज़बूत ग्रामीण विकास की नींव डालने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 2 कदम- डिजिटल इंडिया और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना- देश में समृद्ध गांवों की नींव डालने वाले और विकसित भारत की सोच को ग्रासरूट तक ले जाने वाले साबित होंगे।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज डिजिटल इंडिया के तहत सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांवों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों केकम्प्यूटराइज़ेशन के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) से लेकर पूरी सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक बनाने का काम मोदी जी ने किया है। श्री शाह ने कहा कि इन दोनों कामों में लगभग सवा दो सौ करोड़ रूपए की लागत आएगी, जिनमें से ARDBs पर 120 करोड़ रूपए और RCS पर 95 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और मध्यम और दीर्घकालीन ऋण लेने वाले किसानों के लिए आज से एक सरल सुविधा की शुरूआत होगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 2 साल में मोदी सरकार ने सहकारिता में डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से एक दूरगामी सोच के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय बनने के तुरंत बाद सबसे पहले 65000 पैक्स, केन्द्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स और फिर पैक्स के साथ साथ सभी ज़िला और राज्य सहकारी बैंकों का कम्प्यूटराइज़ेशन किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया और अब ARDBs और RCS के कम्प्यूटराइज़ेशन के साथ ही पूरा सहकारिता क्षेत्र आज डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 65000 पैक्स के कम्प्यूटराइज़ेशन के लिए आधुनिक और लोगों के साथ संवाद करने योग्य सॉफ्टवेयर को नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया है और इसी के साथ ये सभी पैक्स इससे जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के कम्प्यूटराइज़ेशन का काम भी पूरा हो चुका है, जिससे इस कार्यालय के सभी काम एक ही सॉफ्टवेयर से हो सकेंगे।

श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के माध्यम से राज्यों, तहसील, ज़िला और ग्रामस्तर पर कोऑपरेटिव्स की सही जानकारी सामने आ जाएगी जिससे सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। उन्होंने कहा किवैक्यूम को भरने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज RCS कार्यालय के कंप्यूटराइजेशन होने के साथ ही इससे राज्यों की स्थानीय भाषाओं में संवाद हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पर उच्चतम स्तर पर ध्यान न देने के कारण ये अपनी भूमिका अच्छे तरीके से नहीं निभा पाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम और दीर्घकालीनऋण के लिए यह एक बहुत उपयोगी व्यवस्था है जो आधुनिक खेती की ओर जाने के लिए किसान को पूंजी मुहैया कराती है। श्री शाह ने कहा कि अगर हम खेती को आधुनिक नहीं बनाएंगे तो न हम उपज बढ़ा पाएंगे और न ही किसानों को समृद्ध कर पाएंगे। श्री अमित शाह ने कहा ARDBs के कंप्यूटराइजेशन से इनकी operational efficiency में बहुत सुधार आएगा, एकाउंटिंग में एकरूपता आएगी और पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार, नाबार्ड द्वारा सभी प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक को एक राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे सभी प्रकार के कृषि ऋण का लिंकेज मजबूत हो सकेगा। श्री शाह ने कहा कि देश के 1851 ARDBs की शाखाओं का कंप्यूटराइजेशन होने से इनसे जुड़े 1 करोड़ 20 लाख किसानों को बहुत फायदा होगा।

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDB) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित ARDB की 1851 इकाइयों को कम्प्यूटरीकृत करने और उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से NABARD से जोड़ने का लक्ष्यरखा गया है। सहकारिता मंत्रालय की यह पहल Common Accounting System (CAS) और Management Information System (MIS) के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को standardized कर ARDB के परिचालन, दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा, इस पहल का उद्देश्य transaction cost को कम करना, किसानों को ऋण वितरण में सुविधा प्रदान करना और योजनाओं की बेहतर monitoring और assessment के लिए real time data access को enable करना है।

वैश्विक कृषि-निर्यात बाजार में मध्यप्रदेश का उदय
बुरहानपुर का केला पहुंचा इराक, ईरान, दुबई, बहरीन, तुर्की

भोपाल : मध्यप्रदेश ने तेजी से वैश्विक कृषि निर्यात बाजार में अपना स्थान बना लिया है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले से इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की को सालाना 30 हजार मीट्रिक टन केले का निर्यात हो रहा है। बुरहानपुर केले की प्रसिद्धि दूर-दूर तक पंहुच गई है। केला उत्पादक किसानों की मेहनत और सरकार की मदद ने बुरहानपुर को एक नई पहचान दिलाई है। लगभग 19000 केला उत्पादक किसान 23,650 एकड़ क्षेत्र में केले की फसल ले रहे हैं। इसमें बुरहानपुर से ही सालाना औसत 16.54 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। एक जिला-एक उत्पाद योजना में केले को शामिल करने के बाद केला उत्पादक किसानों ने उत्साहपूर्वक निर्यात अवसरों का भरपूर लाभ उठाया है।

कृषि निर्यात बाजार में किसानों की गहरी रुचि, कृषि व्यापार के मज़बूत बुनियादी ढांचे और निर्यात कंपनियों की अच्छी उपस्थिति के कारण बुरहानपुर केले को अच्छा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल गया है। यहां मुख्य रूप से जी-9, बसराई, हर्षाली, श्रीमंथी किस्में उगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना में केला उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल रहा है। परिणामस्वरुप बुरहानपुर में 30 केला चिप्स प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हैं। कुछ इकाईयाँ केले का पाउडर भी बना रही हैं और मार्केट की तलाश में है।

बुरहानपुर के प्रवीण पाटिल अच्छे मुनाफे से खुश हैं। उनके पास दापोरा गांव में 60 एकड़ जमीन है, जो बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 16 किमी दूर है। दापोरा एक ग्राम पंचायत है जिसमें लगभग 700 घर हैं। उन्होंने केले की खेती का गुर अपने पिता और दादा से सीखा।

प्रवीण बताते हैं कि पिछले दो सीजन में बाजार भाव अच्छा रहा। बाजार की मांग के अनुसार 2,000 से 2,500 प्रति क्विंटल तक केला बिका। हर सीजन अच्छा नहीं रहता। कई बार मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होता है।

खेती की लागत के बारे में प्रवीण बताते हैं कि यह लगभग प्रति पौधा 140 रु. तक आती है। वे बताते हैं कि 300 से 500 पौधे लगाते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो 450 से 500 क्विंटल तक उत्पादन होता है। अत्यधिक वर्षा, मौसम और खेतों में पानी का भराव केले के पौधों को नुकसान पहुंचाता है, जो कक्यूम्बर मोज़ेइक वायरस - सीएमवी का शिकार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि वायरस लगे पौधों को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

प्रवीण 15 सदस्यों के संयुक्त परिवार में सबसे बड़े हैं। दो छोटे भाई साथ रहते हैं। बड़ा बेटा रोहल पाटिल इंदौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है. छोटा बेटा श्वेतल पाटिल इसी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। दोनों छुट्टी के दौरान कभी-कभी खेती की गतिविधियों में सहयोग कर देते हैं।

प्रवीण आगे बताते हैँ कि बुरहानपुर केले का घरेलू बाजार अच्छा है। हमारा केला नई दिल्ली और हरियाणा तक जाता है। मैं उन लोगों के संपर्क में भी रहता हूं जो कृषि निर्यात करते हैं।

बुरहानपुर से 19 किमी दूर इच्छापुर गांव है जहां केले की खेती करने वाले किसानों की संख्या काफी है। अधिकतर किसान पारंपरिक खेती करते हैं। यहां के 37 वर्षीय किसान राहुल चौहान के पास 25 एकड़ जमीन है। वे बचपन से ही केले की खेती के तौर तरीकों से परिचित हो गये थे। वे 17 सदस्यों के संयुक्त परिवार में रहते हैं। वह चार भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनका बेटा विश्वनाथ प्रताप सिंह चौहान दूसरी कक्षा में पढ़ता है जबकि बेटी प्रिया छठी कक्षा में है। उनके पास एक ट्यूबवेल और एक पारंपरिक कुआं है। वे खेती का अर्थशास्त्र अच्छी तरह जानते हैं। लाभ और हानि के बारे में विस्तार से समझाते हुए वे कहते हैं कि यह सब मौसम और बाजार के व्यवहार पर निर्भर करता है।

कई बार बाजार भाव अच्छे होते हैं लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। कभी फसल अच्छी होती है लेकिन भाव नहीं मिल पाते। वे वायरस हमले के प्रति भी चिंतित रहते हैं और बताते हैं कि सीएमवी वायरस स्वस्थ केले के पौधे के लिए एकमात्र खतरा है। उनका कहना है कि अगर पूर्ण विकसित पौधों में सीएमवी हो तो हमें उन्हें जड़ से उखाड़ना होता है।

राहुल बताते हैं कि वे दिन गए जब पूर्वजों का मानना था कि ज्यादा पौधे ज्यादा उपज देंगे। हम 8x5 फीट जगह में पौधे लगा रहे हैं। प्रति एकड़ 1,200 पौधे लगाते हैं। पहले 1,800 पौधे प्रति एकड़ लगा रहे थे। प्रति पौधे की लागत लगभग 150 रुपये तक आती है। एक एकड़ में 1.5 लाख का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। एक सीजन का लाभ 25 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। इसमें खेती की लागत भी शामिल है।

राहुल आगे बताते हैं कि एक एकड़ खेती की लागत लगभग रु. 70 हजार तक आ जाती है। एक विकसित पौधा 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक के गुच्छे देता है। यदि अच्छी तरह से देखभाल हो जाए तो प्रति गुच्छा 30 से 35 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। उनका मानना है कि केला उत्पादकों के हित में मंडी प्रणाली की कार्यप्रणाली में और सुधार करने की जरूरत है। उपज बेचने में प्रक्रिया में देरी से अच्छे मुनाफे की संभावनाएं प्रभावित होती हैं।

जिला मुख्यालय से 11 किमी दूर शाहपुर गांव के राजेंद्र चौधरी जैसे छोटे किसान भी बहुत संख्या में हैं। उनके पास चार एकड़ जमीन है जिस पर वह 5000 पौधे लगाते हैं। वे औसतन 5 लाख रूपये कमा लेते हैं। उनका कहना है कि पिछले दो-तीन सीजन में बाजार किसानों के लिए बेहद अनुकूल रहा है। उनका बेटा मोहित चौधरी एक स्थानीय प्रबंधन कॉलेज से एमबीए कर रहा है, जबकि छोटे बेटे अनिकेत ने पास के खकनार सरकारी पॉलिटेक्निक से फिटर ट्रेड में डिप्लोमा किया है।

केले के उत्पादन ने केला चिप्स प्रसंस्करण इकाइयों को जन्म दिया है। फिलहाल बुरहानपुर में ऐसी 30 इकाइयां हैं। योगेश महाजन केले के चिप्स बनाने की इकाई मारुति चिप्स चलाते हैं। उनका सालाना टर्नओवर 20 से 25 लाख रुपए है। उनका कहना है कि केले की आसान उपलब्धता और लगातार आपूर्ति ने उन्हें चिप्स बनाने की इकाई खोलने के लिए प्रेरित किया। वे किसानों से सीधी खरीद करते हैं। खरीद दर फसल की आवक के अनुसार बदलती रहती है। खेतों से सीधे खरीद की दर 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्रोसेसिंग के बाद एक किलो चिप्स के पैक की थोक दर 150 रुपये है जबकि बाजार में खुदरा कीमत 200 रूपये प्रति किलो है। बाजार के बारे में उनका कहना है कि केला चिप्स अपनी गुणवत्ता के कारण पसंद किये जाते हैं। चिप्स की गुणवत्ता स्वच्छता, तलने की तकनीक, गुणवत्तापूर्ण खाद्य तेल का उपयोग, कुरकुरेपन पर निर्भर करती है। उनका कहना है कि चिप्स बनाने के काम में जरूरतमंद स्थानीय महिलाओं को लगाया जाता है।प्रशिक्षण के बाद वे अब कुशल हो गई हैं।राहुल बताते हैं कि उनके पास अच्छा ग्राहक आधार है और भोपाल जैसे महानगरों में कुछ आउटलेट भी हैं। बुरहानपुर केले के चिप्स अब अपनी पहचान बन चुके है। उनका कहना है कि केला उत्पादक किसानों को अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए। इससे हमारी चिप्स इकाइयां भी अच्छे से चल चलेंगी। हाल ही में जब बुरहानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर एक जिला-एक उत्पाद पुरस्कार-2023 में स्पेशल मेंशन श्रेणी का पुरस्कार मिला तो गोकुल चौधरी, तुषार पाटिल जैसे केला उत्पादक किसान दिल खोलकर खुश हुए।

कृषि में समस्याओं से निपटने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

नई दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रणालियों को नियोजित किया है। इसके अंतर्गत अपनाई गईं कुछ पहलें नीचे दी गई हैं:

i. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में प्रश्नों में किसानों की सहायता के लिए 'किसान ई-मित्र' एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-संचालित चैटबॉट है। यह समाधान कई भाषाओं में सहयोग करता है और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सहायता के लिए विकसित हो रहा है।

ii. जलवायु परिवर्तन के कारण उपज को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली लागू की गई है। यह प्रणाली फसल संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिससे स्वस्थ फसलों के लिए समय पर सहायता संभव हो पाती है।

iii. चावल और गेहूं की फसल के लिए उपग्रह, मौसम और मिट्टी की नमी डेटासेट का उपयोग करके फसल स्वास्थ्य मूल्यांकन और फसल स्वास्थ्य निगरानी के लिए खेत की तस्वीरों का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित विश्लेषण किया जाता है।

600 एलएमटी से अधिक की धान की खरीद और 1,30,000 करोड़ रुपये से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रवाह से 75 लाख किसान लाभान्वित हुए

नई दिल्ली। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 (खरीफ फसल) के दौरान 600 लाख एमटी से अधिक धान की खरीद पूरी हो चुकी है। इससे 1,30,000 करोड़ रुपये से अधिक का एमएसपी परिव्यय प्रदान करके 75 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। यह खरीद अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी।

600 मीट्रिक टन धान की खरीद के मौजूदा स्तर के साथ, केंद्रीय पूल में पीएमजीकेएवाई/टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगभग 400 एलएमटी वार्षिक आवश्यकता की तुलना में 525 एलएमटी से अधिक चावल उपलब्ध है। सरकार की ओर से मार्च, 2024 में शुरू होने वाले आगामी रबी सीजन के दौरान गेहूं की अधिकतम खरीद के लिए भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के परामर्श से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादों के निर्यात में मिली बड़ी सफलता

ओमान के लिये शुष्क सोयाबीन दूध पावडर की पहली खेप रवाना

भोपाल : कृषि प्र-संस्कृत खाद्य निर्यात प्राधिकरण (एपीडा) ने प्रदेश के कृषि निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। एपीडा के सहयोग से मध्यप्रदेश के एक्सपोर्टर द्वारा ओमान के लिये शुष्क सोयाबीन दूध पावडर की पहली खेप की गाड़ी को हरी-झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एपीडा के जनरल मैनेजर डॉ. वी.के. विद्यार्थी, एपीडा के बोर्ड मेम्बर श्री संतोष गोयल, एक्सपोर्टर मैसर्स बॉयोनाइट्रेंट्स प्रायवेट लिमिटेड भोपाल के प्रतिनिधि और इम्पोर्टर मैसर्स इंटरनेशनल टूरिज्म रेस्टॉरेंट कम्पनी ओमान के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एपीडा निर्यातकों को अपने उत्पाद विदेशों में निर्यात करने में आवश्यक सहयोग मुहैया कराता है। एपीडा की मध्यस्थता से ओमान के साथ बॉयोन्यूट्रेंट (इण्डिया) प्रायवेट लिमिटेड के मध्य दीर्घकालिक अनुबंध हुआ है, जिसमें एक निश्चित मात्रा में शुष्क सोयाबीन मिल्क पावडर नियमित रूप से ओमान भेजा जायेगा। इसका प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलेगा तथा कृषि उत्पादों के निर्यात की नई संभावनाओं का उदय होगा। एपीडा का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुसूचित उत्पादों को बढ़ावा देना है। एपीडा के प्रयासों से देश के विभिन्न राज्यों से कई नये उत्पाद विदेशों में सफलतापूर्वक निर्यात किये जा रहे हैं।

ओमान को शुष्क दूध पावडर भेजने वाले निर्यातक ने बताया कि देश में उच्च प्र-संस्करण लागत के कारण सीमित मात्रा में विनिर्माण कम्पनियाँ सोया मिल्क पावडर का उत्पादन कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी कम्पनी देश में रियल, हल्दीराम और अन्य कम्पनियों को सोया मिल्क पावडर की आपूर्ति कर रहे हैं।

ओमान के इम्पोर्टर ने बताया कि मध्य पूर्व के देशों में भारतीय उत्पादों की बहुत माँग है। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता मानकों और खाद्य सुरक्षा मानदण्डों के पालन में कड़ाई होने से बाजार में स्थापित होने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के एक्सपोर्टर द्वारा सप्लाई किया जा रहा सोया मिल्क पावडर सभी परीक्षण मानकों पर खरा उतरा है। इसीलिये कम्पनी से दीर्घकालिक अनुबंध किया है और आशा है कि भविष्य में और भी इम्पोर्टर भारतीय उत्पादों का आयात करेंगे।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन

जबलपुर : रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन 5 फरवरी से 1 मार्च तक किया जायेगा। किसान समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय करने हेतु अपना पंजीयन निर्धारित की गई सहकारी समिति, विपणन संस्था, एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेन्टर तथा किसान एप्प के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे।

सिकमी अथवा बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल निर्धारित सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था स्तर पर ही उपलब्ध होगी। कृषक पंजीयन हेतु जिले में 59 सहकारी समितियां एवं विपणन संस्थाएं निर्धारित की गई है।

तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों, निर्धारित सहकारी संस्थाओं तथा विपणन सस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों तथा एम.पी. किसान एप्प पर पंजीयन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने किसानों से समर्थन मूल्य पर अपनी उपज विक्रय करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीयन कराने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए 3 सुविधाओं का केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा द्वारा शुभारंभ

किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सतत काम कर रहा कृषि मंत्रालय- श्री मुंडा

किसानों की ताकत से ही देश का साम्थ्र्य और मजबूती- केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत केंद्रीयकृत "किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल", कृषि-बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफार्म सारथी (SARTHI) एवं कृषि-समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) प्लेटफॉर्म का दिल्ली में शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि यह देश गांवों का देश है, किसानों का देश है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। किसानों को उन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए श्री मुंडा ने कहा कि किसानों के साम्थ्र्य, ताकत, मजबूती से ही देश का साम्थ्र्य व मजबूती है। इसे ध्यान में रखते हुए व कृषक समुदाय की उन्नति को रेखांकित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय काम कर रहा है। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस दिशा में सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में अवसर मिल रहा है कि तकनीकी रूप से भी किसानों को सशक्त बनाने में सहयोगी बनें। किसानों से डिजिटली जुड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसी नवाचार के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन, सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क एवं एलएमएस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देती है व इसे अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी, आय-उन्मुख व लचीला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कृषि मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल हैं। साथ ही, 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बागवानी मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के जरिए भी किसानों की जरूरतों व लाभ के लिए मंत्रालय काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना व कृषि कार्यों में जोखिम कम करना है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र को ज्यादा ग्रोथ के लिए जहां निवेश की जरूरत है, वहीं प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके लिए काफी कारगर साबित हुई है। योजना के प्रारंभ से अभी तक इसमें 15 करोड़ से ज़्यादा किसान जुड़े हैं और अब तक किसानों के 29,237 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले 1.52 लाख करोड़ रु. के दावों का पेमेंट किया गया है।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारें किसान प्रीमियम के रूप में केवल 1 रुपये के साथ सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करके किसानों का समर्थन करने के लिए आगे आई हैं। पिछले कुछ समय में योजना के क्रियान्वयन में सुधार के प्रयास भी लगातार जारी हैं। सरकार प्रतिबद्ध है कि कृषि क्षेत्र में ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाएं, जिससे किसानों के लिए जोखिम कम हो व आय बेहतर हो सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि किसानों की समस्या का समाधान डाटा के साथ करने में समर्थ हों। इसका विशेष ध्यान रखें कि हमारे अन्नदाता निराश नहीं हो, बल्कि उनका सरकार के प्रति विश्वास और बढ़े, उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनके पीछे पूरी ताकत से सरकार खड़ी है और वे आगे बढ़ रहे है। कृषि मंत्रालय, प्रधानमंत्री श्री मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहा है। किसान युवा, मातृशक्ति, गरीब सभी के लिए काम हो रहा हैं। कृषि मंत्रालय, संगठित रूप में किसानों के लिए काम कर रहा है, जिसका लाभ देश के अन्नदाताओं को मिल रहा है।

प्रारंभ में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ व कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रितेश चौहान ने स्वागत भाषण दिया। अपर आयुक्त (क्रेडिट) कामना शर्मा ने आभार माना। कार्यक्रम में केंद्र व राज्यों के अधिकारी, बीमा कंपनियों एवं तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा योजना से जुड़े अन्य हितधारक उपस्थित थे।

रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

नई दिल्ली। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) नामक एक उप-योजना के माध्यम से 2019-2020 से प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है। देश भर में बीपीकेपी के तहत 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती के लिए अब तक 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मंजूरी दी गई है और 70.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। गंगा कॉरिडोर के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार ने बीपीकेपी को बढ़ाकर एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) तैयार किया है।

किसानों के लाभ के लिए, भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा दे रही है जो उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, दक्षता में सुधार करने, फसल की उपज बढ़ाने और संचालन की लागत को कम करने में मदद करेगा।

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) के तहत ड्रोन की खरीद की लागत के 100 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति ड्रोन की खरीद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), राज्य और अन्य केंद्र सरकार के कृषि संस्थानों/विभागों और कृषि गतिविधियों में लगे हुए भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अधीन संस्थानों द्वारा किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए किसान ड्रोन की लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। इन कार्यान्वयन एजेंसियों को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर का आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाता है जो ड्रोन खरीदना नहीं चाहते हैं लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), हाई-टेक हब, ड्रोन निर्माताओं और स्टार्ट-अप से प्रदर्शन के लिए ड्रोन किराए पर लेंगे। ड्रोन प्रदर्शनों के लिए ड्रोन खरीदने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों का आकस्मिक व्यय 3000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित है। किसानों को किराये के आधार पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, किसानों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों की सहकारी समिति के तहत सीएचसी द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए 40% की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये प्रति ड्रोन तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर ड्रोन की खरीद के लिए लघु और सीमांत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और उत्तर-पूर्वी राज्य के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एसएमएएम के तहत, किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 141.39 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है, जिसमें किसान ड्रोन की खरीद और 100 केवीके, 75 आईसीएआर संस्थानों और 25 एसएयू के माध्यम से किसानों के खेतों पर उनके प्रदर्शनों के आयोजन के लिए आईसीएआर को जारी किए गए 52.50 करोड़ रुपये शामिल हैं। किसानों को सब्सिडी पर 461 किसान ड्रोन की आपूर्ति और किसानों को ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 1585 किसान ड्रोन सीएचसी की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया गया है। देश भर में आईसीएआर के 193 संस्थानों द्वारा 263 एग्री-ड्रोन खरीदे गए हैं। इन संस्थानों के 260 कर्मियों ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण लिया है। कृषि में ड्रोन के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, इन संस्थानों ने 16,471 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करते हुए पोषक तत्वों, उर्वरकों, रसायनों (कीट और कीटनाशक) अनुप्रयोगों पर 15,075 ड्रोन प्रदर्शन किए हैं।

सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना "नमो ड्रोन दीदी" को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। कुल 15,000 ड्रोनों में से, पहले 500 ड्रोन 2023-24 में लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) द्वारा खरीदे जाएंगे, जो चयनित एसएचजी को वितरण के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। इस योजना के तहत, 2024-25 और 2025-26 के दौरान शेष 14500 ड्रोन प्रदान किए जाएंगे और महिला एसएचजी को खरीद के लिए ड्रोन की लागत का 80 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में और उपकरण/सहायक शुल्क के लिए 8.0 लाख रुपये तक दिये जाएंगे। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचित किया गया है, उन्होंने पायलट आधार पर पूर्ण वाटरशेड और जनजातीय विकास परियोजनाओं में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड और जनजातीय विकास निधि के तहत जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। संयोग से, जिन गैर सरकारी संगठनों ने वाटरशेड और जनजातीय विकास परियोजनाओं को लागू किया है, वे जीवा कृषि-पारिस्थितिकी कार्यक्रम (प्राकृतिक खेती) की कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने इंदौर .....

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उसको विस्तारित करने के लिये सहकारिता विभाग अब नए कलेवर और नयी सोच के साथ कार्य करेगा। इसके लिये बहुवर्षीय रोडमैप बनाकर सहकारिता आंदोलन में नयी तकनीक को शामिल करते हुए प्रक्रिया सुधार के कार्य किये जायेंगे। सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार किया जायेगा।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अधिकारी विभाग में नवाचार करते हुए नयी सोच, पारदर्शिता एवं पूर्ण ईमानदारी से निष्ठावान होकर कार्य करें। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें। को-ऑपरेटिव बैंकों को प्रायवेट बैंकों के अनुरूप बनायें। इसे नए कलेवर में कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह प्रस्तुत करें। समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य एवं व्यवहार में बदलाव लाये। जन-कल्याण के अधिक से अधिक कार्य करें। सहकार से समृद्धि की ओर प्रदेश को आगे बढ़ाये।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के रिक्त सभी पदों की पूर्ति सुनिश्चित करें। सहकारी समितियों में अधिक से अधिक महिला सदस्यों को जोड़ें। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सहकारी सोसायटियों का गठन करें। इन्हें आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ायें। को-ऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से मोबाइल साँची पार्लर की स्थापना कराई जाये। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सहकारिता को बढ़ावा दिया जाये।

उन्होंने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि गेहूं खरीदी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित हो कि गेहूं खरीदी कार्य पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ईमानदारी से हो। उन्होंने कहा कि समय पर पूर्ण ऋण चुकाने वाले कृषकों और सदस्यों को सम्मानित किया जाये।

बैठक में सहकारिता आयुक्त श्री आलोक कुमार सिंह, अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम श्री सावन सोनकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अब किसान फसल की जानकारी MPKISAN App के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे

इन्दौर : "मेरी गिरदावरी- मेरा अधिकार" में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी MPKISAN App के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जायेगा। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा। मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार में किसान को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपीकिसान एप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

किसान एप पर लॉगिन कर फसल स्व-घोषणा, दावा आपत्ति ऑप्शन पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के लिये प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला/तहसील/ग्राम/खसरा आदि का चयन कर एक या अधिक खातों को जोड़ा जा सकता है। खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी एप में उपलब्ध होगी। उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर ए आई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी। किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोयी गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है।

विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी मजबूती : सारंग

भोपाल। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का बजट को लेकर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल्याणकारी और विकासशील सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है। 'जन–जन की आशाओं और आकांक्षाओं' को पूरा करने वाला यह बजट 'विकसित भारत' के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सी.एच.सी.डी.एस) अंतर्गत गुरुशिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

महिला अभ्यार्थियों को जूट क्राफ्ट प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाण पत्र वितरित किये गये

भोपाल। विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या० द्वारा आयोजित गुरूशिष्य हस्तशिल्प 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 7.12.2023 से 6.2.2024 तक प्रबंध संचालक, राज्य संघ के मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक आयोजित किया गया।

श्रीमति मीनाक्षी बान, राज्य संघ, सी.एच.सी.डी.एस परियोजना प्रभारी एवं श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव ने बताया कि, दिनांक 7.12.2023 से 6.2.2024 तक (50 दिवसीय) चिन्हित 30 महिला प्रतिभागियों को जूट शिल्प पर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान प्राप्त मास्टर ट्रेनर श्रीमती नीतू यादव एवं श्रीमती संगीता यदूवंशी, सहायक के द्वारा कारपेट, मेट्स, ट्रेंडी बैग, लेम्पसेडस, फूटवियर, ग्रिटिंग कार्ड, चोटी एवं जूट शिल्प के विभिन्न उत्पादों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य श्री ए. के. जोशी, पूर्व प्राचार्य, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, का विशेष सहयोग रहा।

जैविक खेती और सहकारिता

इन्दौर। आर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नही होता है। इसमें खाद व कीटनाशक भी जैविक ही इस्तेमाल किये जाते है। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक बनी रहती है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित नही होता। इससे कृषि लागत घटती है तथा उत्पाद की गुणवत्ता बढती है, जिससे किसानो को अधिक लाभ होता है । केमिकल से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है तथा इससे उपजी फसलो से इंसानो को बीमारियो का खतरा भी रहता है। इसलिये इन केमिकल्स को धीमा जहर कहा जाता है। यही वजह है कि अब लोग धीरे धीरे जैविक खेती की ओर आकर्षित हो रहे है । आधुनिक युग में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर अल्बर्ट हॉवर्ड को आधुनिक जैविक खेती का जनक माना गया है।

भारत में जैविक खेती की शुरूआत का श्रेय डॉक्टर जयपाल आर्य को दिया जाता है जो भाई की कैंसर से मृत्यु होने के पश्चात जैविक खेती की और आकर्षित हुऐं । जैविक खेती में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है। अभी तक 1.19 मिलियन किसान भारत में इसके अंर्तगत पंजीकृत हो चुके है। जैविक खेती उपज की दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। भारत का पहला शत प्रतिशत जैविक खेती राज्य सिक्किम है तथा लक्षद्वीप पहला केन्द्र शासित प्रदेश है । भारत सरकार ने जैविक खेती को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा देने के लिये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत जैविक उत्पादो के लिये राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना की मंजूरी दी है। समिति प्रामाणिक जैविक उत्पाद प्रदान करके जैविक कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रबंधन करेगी।

भारत और विदेशो में ऐसे उत्पादो की मांग और खपत क्षमता का आंकलन करेगी। किफायती लागत पर सुविधा, परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से ब्रांडिंग व विपणन कार्य करेगी। इस समिति का नाम नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एन.सी.ओ.एल.) है । जिसका पंजीकृत कार्यालय गुजरात के आणंद में है । इस समिति के पांच प्रर्वतक है- अमूल, नाफेड, एनसीसीएफ, एनडीडीबी और एनसीडीसी । इसमें एनडीडीबी मुख्य प्रर्वतक है। समिति ने 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत कई उत्पाद लांच किये है। जिन्हें विभिन्न आउटलेट व ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से बेचा जा रहा है। प्राप्त मुनाफे की 50 प्रतिशत राशि किसानो को प्रदान की जाती है।

वैश्विक जैविक उत्पाद बाजार का आकार 10 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान है जिसमें भारत का योगदान 27,000 करोड़ रूपये है। एनओसीएल द्वारा एक छत के नीचे सभी जैविक उत्पादो के लिये खुदरा दुकानो का नेटवर्क देश विदेश में शुरू किया है। आने वाले समय में 'भारत ऑर्गेनिक्स' दुनिया के जैविक उत्पाद बाजार में सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा ब्रांड बन जायेगा ऐसी उम्मीद है। सभी पैक्स, एफपीओ और प्रगतिशील किसानो को इस संगठन से जुडकर 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड को मजबूत करना चाहिये तथा इसके माध्यम से खुद को समृद्ध बनाना चाहिये।

शिरीष पुरोहित
प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण
केन्द्र, नौगांव

सहकारिता विभाग के जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधकों हेतु बी - पैक्स के मॉडल बायलॉज एवं मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 पर प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। प्रमुख सचिव, सहकारिता मध्यप्रदेश शासन एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 एवं बी-पैक्स के मॉडल बायलॉज के प्रावधान व उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01/02/2024 से 02/02/2024, 05/02/24 से 06/02/24, 07/02/24 से 08/02/24, 12/02/2024 से 13/02/2024 तक कुल 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सफलतापूर्वक आयोजित किये गयें। जिसमें सहकारिता विभाग के लगभग कुल 96 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधकों एवं पैक्स प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण पर जानकारी देते हुए श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या0 भोपाल द्वारा बताया गया कि "सहकार से समृद्धि" की दिशा में सहकारिता विभाग म.प्र. के सहकारी क्षेत्र से जुड़े जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक एवं पैक्स प्रबंधक को निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिता पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। जिसमें श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा बी- पैक्स के नवीन बायलाज अनुसार बी - पैक्स की प्रमुख गतिविधियां एवं क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश, श्री प्रदीप कुमार नीखरा से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 क्या है, इसकी आवश्यकता, विजन, मिशन एवं उददेश्य व सहकारी नीति के प्रमुख प्रावधान, विषय विशेषज्ञ श्री श्रीकुमार जोशी, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता बी - पैक्स की उपविधि, सहकारी अधिनियम व नियम के प्रावधान सहकारी नीति के संदर्भ में, एवं मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 क्रियान्वयन हेतु एक्शन प्लान का क्रियान्वयन, सहकारिता के विशिष्ठ सेक्टर जैसे - कृषि साख, स्वॉट एनालिसिस, बीज उत्पादन, डेयरी, मत्स्य एवं लघु वनोपज एवं किसान उत्पादक संगठन (एफ. पी.ओ.), श्री अरविंद सिंह सेंगर, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा बी-पैक्स नवीन बायलॉज की आवश्यकता व उद्देश्य एवं सेवाऐं, श्री अशोक शर्मा से.नि. क्वालिटी कंट्रोलर, म.प्र. वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल, द्वारा वृहद भण्डारण योजना को बी - पैक्स में लागू करना, श्री अतुल श्रीवास्तव, साईबर विशेषज्ञ, राज्य साईबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा साईबर अपराध पर श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं श्री संतोष येडे राज्य समन्वयक द्वारा श्री सेवड़ी सेवा सहकारी मण्डली सूरत गुजरात मल्टी सर्विस सेंटर (PACS as MSC) के रूप में कार्य कर रहें गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र में प्रबंध संचालक एवं महाप्रबंधक राज्य संघ द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान पर प्रतिभागियों से खुली चर्चा की गई एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक लिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक, एवं श्री विनोद कुशवाहा, जिला सहकारी प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षक केन्द्र भोपाल द्वारा किया गया। श्रीमती रेखा पिप्पल, व्याख्याता, श्री अरूण कुमार जोशी, से.नि. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, श्री धनराज सैंदाणे, श्री प्रवीण कुशवाहा, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री ज्ञानू सिंह, मो. शाहिद खांन का विशेष सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।